

## नगर नगिम (संशोधन) वधियक, 2022

### प्रलिमिस के लयि:

शहरी स्थानीय नकिय, नगर नगिम, भारतीय संवधिान का 74वाँ संशोधन ।

### मेन्स के लयि:

शहरी स्थानीय नकियों की कार्यात्मक स्वायत्तता के लयि चुनौतियीं ।

## चर्चा में क्यीं?

नगर नगिम (संशोधन) वधियक, 2022 जलद ही संसद में पेश कयिा जाएगा ।

- इसका उद्देश्य नगर नकिय के वभिजन के 10 साल बाद राजधानी दलिली के तीनीं (दक्षणि, उत्तर और पूरव दलिली) नगर नगिमों का वलिय करना है ।

## CENTRE TO DECIDE NO. OF SEATS

- Proposed legislation, likely to be introduced during current Parl session, **seeks to cap no. of seats in combined MCD at 250**
- Centre empowered to decide

- this exact number as well as number of reserved seats
- Key element is the proposed **reliance on e-governance** to improve quality of services

“Delhi govt was troubling the civic bodies by blocking their funds. Now after unification, MCD will be able to get funds —Manoj Tiwari, BJP MP, NE Delhi  
BJP's delaying tactics. It knows it'll lose MCD polls —AAP

## वलिय की पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

- पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 2011 में सरकार ने बेहतर दक्षता के लयि एमसीडी को तीन भागों में बाँटने का प्रस्ताव रखा था ।
  - गृह मंत्रालय द्वारा नवंबर 2011 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद दलिली सरकार ने एक वशिष वधिानसभा सत्र बुलाया और दसिंबर 2011 में दलिली नगर नगिम (संशोधन) वधियक पारति कयिा ।
  - त्रिवभिजन के लयि अंतमि अधसूचना जनवरी 2012 में जारी की गई, जिसके अंतरगत उत्तर और दक्षणि नगर नगिम को 104 वार्ड तथा पूरवी दलिली नगर नगिम को 64 वार्ड प्रदान कयि गए ।
- आवश्यकता:**
  - कई समस्याओं का सामना करना:**
    - तीन भागों में वभिजति एमसीडी को **कई समस्याओं का सामना करना** पड़ा जैसे क सिफाई कर्मचारियीं (स्वीपरस) के वेतन का भुगतान न करना, तीन नागरकि नकियों के बीच संपत्ति का असमान वतिरण, अक्षम प्रबंधन और बढ़ता नुकसान आदी ।
  - असमान वभिजन:**
    - क्षेत्रीय वभिजन और प्रत्येक नगिम की **राजस्व-सृजन क्षमता के संदर्भ** में तीनीं नगर नगिमों का वभिजन असमान था ।

- परणामस्वरूप तीनों नगिमों के दायित्वों तथा उपलब्ध संसाधनों में बहुत अधिक अंतर था।
- **अधिक अंतराल :**
  - समय के साथ यह अंतर बढ़ता गया तथा तीनों नगर नगिमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि होने लगी, जिससे वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं सेवानिवृत्तिलाभों का भुगतान करने में असमर्थ हो गए तथा इस प्रकार दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न होने लगीं।

## नगर नगिम:

### ■ परिचय:

- भारत में नगर नगिम दस लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर/शहर के विकास के लिये ज़रिमेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है।
  - महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर नगिम, सटी कारपोरेशन आदि इसके कुछ अन्य नाम हैं।
- राज्यों में **नगर नगिमों** की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्रशासित प्रदेशों में संसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है।
- नगरपालिका अपने कार्यों के संचालन के लिये **संपत्तिकर राजस्व** पर अधिक निर्भर रहती है।
- भारत में **पहला नगर नगिम वर्ष 1688 में मद्रास** में स्थापित किया गया तथा उसके बाद वर्ष 1726 में **बॉम्बे और कलकत्ता में नगर नगिम** स्थापित किये गए।

### ■ नगर नगिम के निर्माण की आवश्यकता:

- भारत के शहरों में बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास एवं परिवहन जैसी आवश्यक सामुदायिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से संपत्तिकर तथा नशित अनुदान एकत्र करने में सक्षम एक स्थानीय शासी निकाय की स्थापना की आवश्यकता को जन्म दिया है।

### ■ संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संवैधान में **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों** में अनुच्छेद-40 को शामिल करने के अलावा स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था।
- **74वें संशोधन अधिनियम, 1992** ने संवैधान में एक नया भाग IX-A सम्मिलित किया है, जो नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है।
- इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं। इसने संवैधान में एक नई **बारहवीं अनुसूची** भी जोड़ी। 12वीं अनुसूची में 18 मद शामिल हैं।

### ■ संरचना:

- प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को उस विशेष शहर की जनसंख्या के आधार पर वार्ड के रूप में ज्ञात भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधिका चुनाव करता है, जिसे उस वार्ड के निवासियों द्वारा चुना जाता है। वार्ड समिति के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर पाँच वर्ष के लिये किया जाता है।
- एक पार्षद या नगरसेवक एक नशित वार्ड का चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है।
- नगर की जनसंख्या नगर नगिम क्षेत्र में वार्डों की संख्या निर्धारित करती है। इसमें **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और महिलाओं** के लिये सीटें आरक्षित होती हैं।

## वर्षों के प्रश्न

भारत के संवैधान के निम्नलिखित में से कसि प्रावधान का शिक्षा पर प्रभाव है? (2012)

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
2. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

